टेलीडेंसिटी के लक्ष्य

*129. डा॰ मुरली मनोहर जोशी:††
श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्ष 2010 तक के लिए 12 प्रतिशत टेलीडेंसिटी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि जनवरी, 2006 तक उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उक्त उपभोक्ता प्रतिशत समान है; और

(ङ) यदि हां, तो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पृथक-पृथक यह प्रतिशत कितना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ शकील अहमद): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-99 के अनुसार, पूरे देश के लिए वर्ष 2010 तक 15% का टेलीघनत्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 31 जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार समग्र टेलीघनत्व 11.76% तक हो गया है।

(घ) तथा (ङ) जी, नहीं। शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। 31.12.2005 की स्थिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में समग्र टेलीघनत्व 34.77% था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 1.79% था।

Teledensity targets

£†*129. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:††
SHRI RAJ MOHINDER SINGH MAJITHA:

Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

---

††सभा में यह प्रश्न डा॰ मुरली मनोहर जोशी द्वारा पूछा गया।

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Murli Manohar Joshi.

£Question No. 123 and Question No. 129 were taken together.

(a) whether it is a fact that a target of 12 per cent teledensity in the country has been set for the year 2010;

(b) if not, the facts in this regard;

(c) whether it is a fact that the said target has been achieved by January, 2006;

(d) if so, whether the said consumer percentage is equal in the rural and urban areas; and

(e) if so, the percentage thereof in rural and urban areas separately?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (DR. SHAKEEL AHMAD): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) No, Sir. According to the National Telecom Policy-99 (NTP-99), a teledensity target of 15% has been set for the entire country by the year 2010. The overall teledensity has touched 11.76% as on 31st January, 2006.

(d) and (e) No, Sir. The number of telephone connections in urban areas are more than in the rural areas. As on 31.12.2005 the overall teledensity in urban areas was 34.77% as against 1.79% in rural areas.

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, while I compliment the Minister for the accuracy of his figures, the figures suggest a very important question. It seems that they have realised, during the last five years, on an average, about Rs. 12,500 crores out of this tax, and I find from your disbursement figures that you have disbursed only about Rs. 3000 crores. Now, I want to know why this whole thing is not being properly utilised and this discloses a very sad state of affairs so far as your concern with the rural areas are concerned, because this is all meant for rural areas and Rs. 9,000/- crores are lying just unutilised.

डा॰ शकील अहमद: सर, यह सही है कि यू॰एस॰ओ॰ फंड की शुरुआत 1.04.2002 में हुई। मगर जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, 2003 का जो अमेंडमेंट है, वह जनवरी, 2004 में लागू हुआ और रूल्स मार्च, 2004 में बने। इसलिए पहले दो साल, 2002-03 और 2003-04 में 300 करोड़ और 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बाद 2004-05 और 2005-06 में, आप एप्रिशिएट करेंगे कि हमने जो figure दिया है, उसके अनुसार 2004-05 में हम लोग मोर दैन 40 परसेंट

डिस्बर्स कर चुके हैं। इस साल हमारा एस्टिमेटेड कलेक्शन 3034 करोड़ होगा। उसके अगैंस्ट हमारा 1750 करोड़ रुपए के आसपास उसमें डिस्बर्समेंट होगा, जो लगभग 60 परसेंट के आस पास है। इनिशियल के दो-तीन सालों में इसके डाटा कलेक्शन में कुछ परेशानी थी, वह हम लोगों ने पूरा कर लिया है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

डा॰ शकील अहमद: सभापति महोदय, पहले हम लोग यू॰एस॰ओ॰ फंड से सिर्फ बी॰पी॰टी॰ को ही यह सब्सिडी दिया करते थे। इधर हम लोगों ने डायरेक्ट हाऊस-होल्ड लाईन को भी किया है। मोबाइल के जो सेल्यूलर फोन ऑपरेटर्स हैं, उनको हम यू॰एस॰ओ॰ फंड से नहीं देते थे। गवर्नमेंट कंटेम्प्लेट कर रही है कि हम मोबाइल आपरेटर्स को भी इस फंड से सब्सिडी दें, क्योंकि वे भी रूरल एरियाज़ को कवर कर रहे हैं। हम यह सोच रहे हैं। हमारा ऐसा प्लान है। मैं समझता हूं कि इससे रूरल टेलीफोनी में और भी तीव्र गति से बढ़ावा मिलेगा।

श्री सभापति: ठीक है।

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, it is not a very satisfactory answer, but it is some plausible answer; so, we let it go. Now, the next supplementary question is, what is the unit when you are dealing with these rural areas, is it a group of villages; is it one village; or, is it a *taluka, tehsil*? How do you deal with it? Then, considering the number of units that you have been able to furnish with these facilities, please tell us roughly — I don't want an exact percentage — how many rural units have been able to get so far the kind of telecom services, which is your goal to supply to the rural areas?

डा॰ शकील अहमद: सभापति महोदय, जो एस॰डी॰सी॰ए॰ होता है, शॉर्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरियाज़, तो हमारे जो एरियाज़ इकोनॉमिकली वायबल नहीं हैं, उनकी संख्या 1685 है। हमने उन एरियाज़ में यू॰एस॰ओ॰ फंड से पैसा देकर यह किया है, ताकि जो हमारे गांव के, देहात के, रूरल एरिया के लोग हैं, उनको यह सुविधा पहुंचे। महोदय, आपको, इस सदन को और इस देश को जानकर प्रसन्नता होगी कि टेलीकॉम सेक्टर का अभी तक का सबसे बड़ा टेंडर, लगभग 60 मिलियन मोबाइल के लाइन का टेंडर, बी॰एस॰एन॰एल॰ करने जा रहे हैं। इससे हमारा लक्ष्य है कि 2007 तक 250 मिलियन, मतलब 25 करोड़ फोन हो जाएंगे। आज की तारीख़ में इस देश में एक करोड़ तीस लाख फोन हैं। हमारा लक्ष्य है कि by 2007, we will achieve the target of 250 million, that is, 25 crores, by using these facilities.

SHRI RAM JETHMALANI: The hon. Minister should better look into his accounts, and give us an answer later on, because this is not the answer.

DR. SHAKEEL AHMAD: No, Sir, this is the correct answer. I have explained everything which comes under USO.

SHRI RAM JETHMALANI: The question that I am putting is, please tell us what is your goal for every rural area, and to what extent, have you fulfilled the goal in terms of the number of units, in terms of percentage? नहीं है, तो बोलो कि अभी नहीं है; बाद में दे दूंगा।

DR. SHAKEEL AHMAD: Sir, I have the information and I know the target that is to be achieved. I have told you very clearly that 1685 SDCAs are to be covered by the USO fund; the non-viable, economically non-viable, SDCAs will be covered by the USO fund.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I think the overall impression given by this reply is misleading. First of all, it is not a tax. सर, मैं मंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपके कैबिनेट मिनिस्टर भी मौजूद नहीं हैं, यह चर्चा पहले भी हुई है कि यह जो टेलीडेन्सिटी है, यह ग्रामीण इलाकों में बहुत ही कम है, जिसके अंदर यह यूएसओ लेवी फंड खर्च करना था और अभी-अभी आपने जवाब में कहा कि यूएसओ लेवी फंड मोबाइल आपरेटर के पास जाएगा। सर, पिछले दिनों में इन मोबाइल आपरेटर ने जो इनका रोल-आऊट ओब्लीगेशन था, वह रोल-आऊट ओब्लीगेशन पूरा नहीं किया और अब टीआरएआई और सरकार ने मिलकर उनको छूट भी दे दी है। इसके पीछे कारण क्या है कि जिन लोगों ने अपने वायदे का उल्लंघन किया, जो लोग ग्रामीण इलाके में नहीं ले जाते, जबकि महानगर में 40 टेली डेन्सिटी है और गांव में सिर्फ 1.9 है, why is the Government going all out to actually award them with this additional money from the USO levy? The second part of the question is, where is that money? 12,000 करोड़ इकट्ठा हुआ था और 3,000 करोड़ ही डिस्बर्स हुआ है, तो बाकी 9,000 करोड़ कहां गया? क्योंकि जब फूड का सवाल आता है, फर्टिलाइजर का सवाल आता है, तो तीखा हमला होता है कि सबसिडी नहीं देना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Please, be brief.

श्री नीलोत्पल बसु: सर, यह 9,000 करोड़ रुपया, जो ग्रामीण और गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वह कहां गया?

डा॰ शकील अहमद: सर, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ऑलमोस्ट 3 साल का पीरिएड था 2005, 2006 और 2007, जिसमें 20 परसेंट, 40 परसेंट और फिर 40 परसेंट का था। इसमें कमोबेश टारगेट एचीव हुए हैं, कहीं कहीं टारगेट एचीव नहीं हुआ है और उसके लिए 6 महीने का टाइम उन्होंने मांगा है। हमारे एग्रीमेंट में ही है कि अगर वे नहीं करेंगे, तो जो उनकी सिक्योरिटी मनी है वह हम जब्त कर सकते हैं, हम एग्रीमेंट को टर्मीनेट कर सकते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु: सर, मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। जब उन्होंने अपना यह कारोबार शुरू किया था, तो उसमें जो रोल-आऊट ओब्लीगेशन था और जो ओरीजनल कांट्रेक्ट हुआ था, उसका उन्होंने पूरा उल्लंघन किया है।

डा॰ शकील अहमद: नहीं, पूरा उल्लंघन नहीं हुआ है, सर। कुछ एचीव किया है। मैं जो यह कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कुछ एचीव किया है और उन्होंने 6 महीने का और टाइम मांगा है, जिस पर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... दूसरी बात मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: सर, यह ठीक नहीं है। यह प्रिविलेज का मुद्दा बनता है। मैं बोल रहा हूं, मंत्री जी जो उत्तर दे रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: मंत्री जी यह कह रहे हैं कि पूरा उल्लंघन नहीं हुआ है, कुछ तो हुआ है।

श्री नीलोत्पल बसु: सर, हो रहा है। यही तो हमारी आपत्ति है कि जिन लोगों ने अपना काम नहीं किया है, जो वायदा किया था उसका उल्लंघन किया है, उनको आज सरकार डिसीजन लेकर पुरस्कृत कर रही है। You are awarding the people who have made violations.

डा॰ शकील अहमद: सभापति महोदय, मैं इस हाऊस को और इस हाऊस के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि यूएसओ फंड से, अभी तक जो 98 परसेंट पैसा है, वह गवर्नमेंट सेक्टर यू, बीएसएनएल को गया है, प्राइवेट ऑपरेटर को बहुत पैसा नहीं गया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: एक पैसा नहीं जाना है। ....(**व्यवधान**)...

डा॰ शकील अहमद: सर, यह इम्प्रेशन डवलप करने की कोशिश की जा रही है कि 98 परसेंट के आसपास पैसा बीएसएनएल को गया है। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ रुपया है, यह 12,000 करोड़ नहीं है बल्कि वर्ष 2004-05 तक 7,000 करोड़ के आसपास था और यह पैसा डीओटी में नहीं है बल्कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, फाइनेन्स मिनिस्टरी के पास है। फाइनेन्स मिनिस्टरी के साथ मिलकर, हम दोनों मिलकर ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: ठीक है। डा॰ मुरली मनोहर जोशी।

श्री नीलोत्पल बसु: सर, यह कानून के मुताबिक फाइनेन्स मिनिस्टर के पास नहीं होना चाहिए।

डा॰ शकील अहमद: नहीं, यही है। जो यूएसओ फंड बना था, सभापति महोदय, वह इसीलिए बना, ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: सर, जवाब नहीं मिला। ...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरा भी एक प्रश्न है और इस संबंध में जिसका मंत्री जी ने उत्तर दिया है, तो इस उत्तर को और अपने प्रश्न को मिलाकर प्रश्न करना चाहूंगा।

श्री सभापति: जो प्रश्न अभी चल रहा है, अभी तो आप इसी प्रश्न तक सीमित रहिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, मंत्री महोदय ने अभी यह उत्तर दिया है कि उन्होंने 12,000 करोड़ इकट्ठे किए USO Fund के अंतर्गत, उसमें से 2000 करोड़ खर्च हुए। तो एक सवाल यह है कि बाकी 10,000 करोड़ कहां गए? यह रुपया आया किसलिए था? यह आया था टेलि-डेंसिटी को ठीक करने के लिए। आप कहते हैं कि टेलि-डेंसिटी का टारगेट 31.01.2006 तक 11.76 परसैंट प्राप्त हुआ है और इसका आंकड़ा यह है कि यह गांवों में है केवल 1.79 परसैंट और शहरों में है 34.79 परसैंट। तो यह जो आप टेलि-डेंसिटी का 12-15 परसैंट टारगेट रख रहे हैं, इसमें कहीं गावों का हिसाब है या नहीं? There is no progress in the tele-density of the rural area, उसमें तो है ही नहीं, 1.79 परसैंट।

श्री सभापति: ठीक है, मंत्री जी को बताने दीजिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: यानी हजार में 1.79 परसैंट और मेरे सवाल का दूसरा भाग यह है कि आपने जो 10,000 करोड़ रुपया फाइनैंस मिनिस्ट्री के पास कहा, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इसको बजटरी डेफिसिट को पूरा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं या जनता का काम करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं?

डा॰ शकील अहमद: सभापति जी, USO Fund को खर्च करने की जहां तक बात है, सरकार जो होती है यह एक कांटिन्यूड प्रोसैस होता है। अगर आप 2002-03 को देखें, जब NDA की सरकार थी, जो उसने मात्र 300 करोड़ रुपया खर्च किया। 2003-04 में भी जब NDA की सरकार थी, उसने खर्च किया 2000 करोड़ रुपया। UPA की गवर्नमेंट 2004-05 में आई, जिसने 40 परसैंट, 1314 करोड़ रुपया खर्च किया ...(व्यवधान)... और इस साल हम लोगों ने 3000 करोड़ रुपए, 3400 करोड़ के बदले 1750 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी 60 परसैंट के आसपास खर्च किया है। ...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: जहां आपने खर्च किया, वहां आम आदमी के साथ आपका हाथ नहीं था। ...(व्यवधान)... यानी आपने रुपया खर्च किया सिर्फ शहरों के अंदर, सिर्फ शहरों की टेलि-डेंसिटी बढ़ाने के लिए, बड़े आदमियों की टेलि-डेंसिटी बढ़ाने के लिए खर्च किया। ...(व्यवधान)...

डा॰ शकील अहमद: सर, मैं ...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: आम आदमी के लिए आपने क्या किया? ...(व्यवधान)...

डा॰ शकील अहमद: सर, मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर हमारे माननीय सदस्य ने इसकी चर्चा की, इसलिए मैंने यह कहा।

श्री सभापति: श्री बी॰जे॰ पंडा। ...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, मंत्री जी यह बताएं कि 10,000 करोड़ रुपए का इन्होंने क्या किया?

श्री सभापति: वह उन्होंने बता दिया, सब बता दिया। ...(व्यवधान)... श्री बी॰जे॰ पंडा। ...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, उन्होंने नहीं बताया कि 10,000 करोड़ रुपए, जो आपने फाइनैंस मिनिस्ट्री को दिए, वहां उनका क्या हो रहा है?

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है। जोशी जी, आप दोबारा पूछ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन आ रहा है। श्री बी॰ जे॰ पंडा।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: आम आदमी की टेलि-डेंसिटी खस्ता करके खास आदमी की आप मदद कर रहे हैं।

SHRI B.J. PANDA: Sir, by non-disbursement of the USO fund, apart from the loss to the citizens in rural areas, the biggest harm has been done to the public sector unit particularly the Bharat Sanchar Nigam Limited which is operating in these rural areas. Cities, towns in a State like Orissa, which are C-Category circles, till today, after 12 years of the Telecom Policy since 1994, do not yet have wire line operations from any of these private sector operators. The hon. Minister has pointed out that 98 per cent of the money has been disbursed to public sector. But the point is, 98 per cent of what? It is 98 per cent of only 25 per cent which has been disbursed. Out of more than Rs. 12,500 crore which has been raised, only Rs. 3000 odd crore has been disbursed. So, 98 per cent of 25 per cent is hardly 22 or 23 per cent of the money that has been given. It means the BSNL deserved, at least, three times more during these past few years which it has not got. Will the hon. Minister assure that the BSNL be given priority for the further funds to be disbursed and not the private sector companies to be given on an equal footage, and by what time will this gap be made up?

डा॰ शकील अहमद: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं कि USO Fund, मैंने अपने उत्तर में बताया है कि 98 परसैंट BSNL को गया है, वह ठीक है and I have explained the reason for the delay. इसलिए जो हमारे पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वे इसको करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमिटिड हैं। लेकिन चूंकि हमने ही प्राइवेट ऑपरेटर्स को लाइसैंस दिया है तो लैवल प्लेइंग फील्ड उनको भी देना पड़ेगा, उनके साथ भी हम किसी तरह से इंडस्ट्री को बढ़ने से रोकना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा BSNL कम्पीट करके इस देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा पहुंचाएं, लेकिन जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, चूंकि हम लाइसैंसिंग अथॉरिटी हैं, मैं यहां BSNL को रिप्रजेंट नहीं कर रहा हूं, I am representing the Government of India, तो हमारे PSU और हमने जिनको भी लाइसैंस दिया है, उनके साथ हम कुछ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जो सरकारी कम्पनी है BSNL और MTNL, इनको प्रोत्साहित करने के लिए हम हर मुमकिन प्रयास करेंगे।

*124[*The questioner (Shri T.T.V. Dhinakaran) was absent. For answer vide page* 33.]

Strikes called by Delhi Bar Association

*125. SHRI AMAR SINGH:††
SHRI ABU ASIM AZMI:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that lawyers belonging to Delhi Bar Association often resort to strike even on trivial matters and if so, the number of times they had gone on strike during the last two years and on what grounds;

(b) whether it is also a fact that Delhi Bar Association has stalled the functioning of the courts whenever efforts have been made at introducing judicial reforms and if so, for how many days; and

(c) what action Government have taken against the lawyers who had threatened to shut down Tis Hazari and Rohini Courts during January, 2006?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) to (c) A Statement laid on the Table of the House.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Amar Singh.